

Ref: JPVL:SEC:2021

7th August, 2021

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
"Exchange Plaza", C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai -400 051

The Manager,
Listing Department,
BSE Limited,
25th Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: JPPOWER

Scrip Code: 532627

Sub: Submission of Newspaper Advertisements pertaining to publication of Financial Results for the Quarter ended on 31st June, 2021

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements pertaining to publication of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021, published in Financial Express (English), Jagran-Bhopal, Jagran-Rewa and Jansatta (Hindi) on 7th August, 2021.

The aforesaid Newspaper Publication have already uploaded on Company's website.

Please take the aforesaid information on records of the Exchanges.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jaiprakash Power Ventures Limited



(Maheshwari Chaturvedi)
Addl. G.M. and Company Secretary



Encl: As above

अशोकनगर में 40 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला, हेलीकाप्टर नहीं भर पा रहे उड़ान, रेस्क्यू में आ रही दिक्कत

अब पार्वती नदी उफान पर, गुना में 8 गांव डूबे अशोकनगर और विदिशा में भी हालात खराब

छतरपुर-टीकमगढ़ में नदी के किनारे के गांवों में अलर्ट, सीएम ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर मांगी मदद



दतिया में टूटा पुल...



सिरोंज: घरों में भरा पानी..

प्रतिपक्ष टीम, भोपाल। ग्वालियर-चंबल में बाढ़ के बीच मध्यप्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। पार्वती नदी उफान पर आ गई है। इससे गुना के 8 गांवों में पानी घुस गया है। रास्ते बंद हो गए हैं। यहाँ सोढ़ी नाम का गांव टापू बन गया है, जहाँ 180 लोग फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ बुलाई गई है। 450 लोग राहत शिविरों में लाए गए हैं। इसके अलावा, अशोकनगर और विदिशा जिले में भी हालात बिगड़ गए हैं। गांवों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। विदिशा में संजय सागर डैम के 7 गेट खुलने से शमशाबाद, सिरोंज और गंजबासोदा में हालात खराब हो गए हैं। छतरपुर और टीकमगढ़ में सुजारा बांध पानी से भर गया है। घसान नदी में बाढ़ की स्थिति है। इसकी वजह से दोनों जिलों में नदी के किनारे वाले गांवों को अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि टूटन गांव के 15 और मुगावली गांव के 25 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकालकर राहत शिविर में पहुंचाया गया है। उधर, शिवपुरी-ग्वालियर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के गुना-ग्वालियर रेल खंड पर ट्रेनों पर असर पड़ा है। इसके चलते पाडरखेड़ा-मोहाना के बीच ट्रेक उखड़ गए हैं। रेल ट्रेक का सुधार कार्य किया जा रहा है। इस कारण इस रेल खण्ड पर चलने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त एवं कुछ गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। रेनवे ट्रेक पर पानी भरने से इंदौर-देहरादोन समेत चार ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है।



विदिशा : नाव से रेस्क्यू..

ग्वालियर-चंबल में फिर भारी बारिश के आसार
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके असर से शनिवार को ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों के साथ राजगढ़ जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि गुरुवार-शुक्रवार के मुकाबले बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि वेदर सिस्टम कमजोर हो रहा है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश की गतिविधियां धीमी पड़ जाएंगी।

पानी भर गया है। गौशाला की दीवार तोड़कर गांवों को रेस्क्यू किया गया। तेज बहाव में बह जाने से 2 गांव की मौत हो गई। शहर की दो दर्जनभर बस्तियां जलमग्न हो गई हैं।

विदिशा : बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू
पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जिले में बाढ़ आ गई है। जिले की सभी नदियां और नालों के उफान पर आने से पुल और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। जिला मुख्यालय का सड़क संपर्क अधिकांश तहसीलों का गांव से कट गया है। जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार कुरवाई में 4 गांव का संपर्क कट गया है, हालांकि इन गांवों में फंसे 425 लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। वहीं सिरोंज में 8 गांवों में 250 लोग फंसे हुए, जहां से 124 लोगों को निकाल लिया गया है, बाकी 126 को निकाला जा रहा है। राजगढ़ जिले में लगातार 4 दिन से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से खिलचौपुर की गाड़गांवा नदी उफान पर है। नदी पर बना छोटा पुल पानी में डूब चुका है। हालात यह हैं कि नदी पर बने बड़े पुल तक पानी पहुंचने लगा है।

सीएम ने शाह से कहा-जल्द भेजें एनडीआरएफ की टीम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर बाढ़ बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजने का अनुरोध किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। अशोकनगर जिले में बाढ़ में लगभग 50 लोग फंसे हैं और तेज बारिश के कारण वायुसेना का हेलीकाप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। अशोकनगर में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की दो टीमों और एक आर्मी कॉलम के आदेश जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ की दो अतिरिक्त टीमों भी अशोकनगर रवाना हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोकनगर सहित गुना, शम्भुपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड आदि में बाढ़ बचाव कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

पानी भरने के बाद चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन

जिले की केथन नदी उफान पर आने से बहादुरपुर सहित अकोदिया, घाटबमूरिया व अन्य गांवों में पानी भर गया। बहादुरपुर की कई दुकानें खाली कराई हैं। वहीं प्रशासनिक अमला ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुगावली-बहादुरपुर मार्ग पर पानी आने के कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। मुगावली की ओर जाने वाला मार्ग के पुल पर लगभग 4 फीट तक पानी भर गया है। बहादुरपुर की पास के गांव अकोदिया पानी की डूब क्षेत्र में आने के कारण वहां से गांव के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है।

पीड़ितों को भोजन व रहने की व्यवस्था करे सरकार

भोपाल, मुप्र। पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावितों को भोजन व रहने की व्यवस्था करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि तीन दिन से सैकड़ों ग्रामीण भोजन आदि की व्यवस्था न होने से भूखों मरने को मजबूर हैं। उनके खाने व रहने की व्यवस्था की जाए। केवल भिंड जिले में ही ग्रामीणों के लगभग 4 हजार मकान और घर गृहस्थी का सामान बर्बाद हो चुका है।



अन्न उत्सव नहीं होना चाहिए: मंत्री

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शनिवार को होने जा रहे अन्न उत्सव कार्यक्रम को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि शायद यह आयोजन नहीं हो पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। जहां एक ओर हमारे लोग पीड़ित हैं, मकान टूट गए, लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने इस बारे में प्रधानमंत्री से बात की है। एकाध घंटे में कैबिनेट में फायनल हो जाएगा। उनके बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सतुजा ने कहा कि मंत्री महेंद्र सिसोदिया भी कमलनाथ की बात का समर्थन कर रहे हैं। उत्सव, जश्न की शौकीन शिवराज सरकार आपदा में भी उत्सव मना रही है।

बाढ़ से महाविनाश, सरकार अन्न उत्सव के आयोजन में लगी

भोपाल, मुप्र। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में 7 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्न उत्सव पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग सहित कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। 1250 से अधिक गांव अभी भी इस भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। आज पूरा देश हमारे प्रदेश में आई इस भीषण बाढ़ से चिंतित है और खुद को संवेदनशील बनाने वाली शिवराज सरकार प्रदेश में 7 अगस्त को भव्य तरीके से अन्न उत्सव मनाने की तैयारियों में जुटी है? राशन दुकानों को गुब्बारे लगाकर, भव्य तरीके से होर्डिंग-पोस्टर लगाकर सजाया जा रहा है, लोगों को निमंत्रण बांटे जा रहे हैं।



आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे नाथ: कमलनाथ शनिवार को ग्वालियर-चंबल संभाग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे शनिवार सुबह 9.45 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर से हेलीकाप्टर से सुबह 10.40 बजे दतिया पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मुलाकात करेंगे।

घर में आग लगने से रेलवे अफसर की पत्नी, बहन और भांजी जिंदा जले, शार्ट सर्किट से आग लगने का अंदेश

जागरण, जबलपुर। गोरबाजार बिलहरी स्थित पिक सिटी में गुरुवार देर रात ढाई बजे आग लगने से 7 साल के मासूम और दो महिलाओं की जलने और दम घुटने से मौत हो गई। वहीं 70 साल की महिला और पश्चिम मध्य रेलवे में तैनात उनके बेटे को कॉलोनी के गार्ड और आसपास के लोगों ने बचा लिया। अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शार्ट सर्किट से लगी होगी। गोरबाजार पुलिस के मुताबिक पिक सिटी गेट नंबर तीन के अंदर मकान नंबर 78 में यह दुखद हादसा हुआ।



डब्ल्यूसीआर जौएम के दफ्तर में तैनात प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर आदित्य सोनी का है। गुरुवार रात को वह घर पर थे। भूतल सहित प्रथम मंजिल का ये मकान बना है। भूतल में उनकी 70 साल की मां कैसर पीड़िता अरुणबाला सोनी किचन के सामने लगे बेडरूम में सो रही थीं। वहीं आदित्य, उनकी पत्नी नेहा सोनी (32), भोपाल निवासी बहन रिती सोनी (37), भांजी परी उर्फ धनविस्ता सोनी (7) पहली मंजिल पर सो रहे थे। कॉलोनी के गार्ड ने देर रात ढाई बजे आदित्य सोनी के मकान में आग देख शोर मचाया। कॉलोनीवासियों के साथ वह पहुंचा तो 70 साल की अरुणबाला सोनी चीख रही थीं। सामने आग लगी थी, जो फैलकर पहली मंजिल तक पहुंच गई थी। वहीं बालकनी से आदित्य सोनी चीख रहे थे। लोगों ने मां-बेटे को किसी तरह निकाला, लेकिन नेहा, रिती और परी कमरे में ही फंस गईं। नेहा बचने के लिए बाथरूम में छुप गई थी, लेकिन धुआं और आग की गरमी ने जान ले ली। नेहा की लाश बाथरूम में मिली। वहीं रिती और परी की लाश बेड पर पड़ी थी। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने पर ड्राइवर अजय कुमार शर्मा दल के साथ मौके पर पहुंचे और

आग बुझाई। आग बुझने के बाद लोग अंदर पहुंचे तो तीनों की लाश मिली। सूचना पर गोरबाजार टीआर सहित केंद्र सीएसपी भावना मरावी, एएसपी गोपाल खंडेल, एएसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, विधायक केंद्र अशोक रोहाणी, नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर, नायब तहसीलदार नीरज कथरिया, एफएसएल डॉ. सुनीता तिवारी और फायर ब्रिगेड प्रभारी कुशाग्र ठाकुर पहुंचे थे। घटना को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। तीनों शवों को मेडिकल कॉलेज की मचरुटी भिजवा दिया गया। वहीं 70 वर्षीय अरुणबाला सोनी की तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आदित्य सोनी की एक बहन वर्षा सोनी आस्ट्रेलिया में रहती हैं। बहन रिती और भांजी परी 10 दिन पहले ही भाई के घर आए थे। पत्नी, बहन व भांजी की मौत से आदित्य सोनी बहदवास से हो गए हैं। मां अरुणबाला सोनी को अभी तीनों मौतों के बारे में नहीं बताया गया है। मकान में आग से फ्लास्टर तक उखड़ गया है। इन्वर्टर सहित टीवी, फ्रिज, धरेलू सामग्री, बिजली की लाइन आदि सब कुछ राख हो गया है। आग भूतल से फैली था।

सिंधिया के अनुरोध पर टीम रवाना

नई दिल्ली, ग्वालियर। ग्वालियर-चंबल अंचल के साथ ही गुना-अशोकनगर जिले में भी लगातार बारिश के चलते हालात खराब हो रहे हैं। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनो जिलों के प्रभारी मंत्री-जिला प्रशासन के सीधे संपर्क में हैं। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से दूरभाष पर चर्चा करके अशोकनगर एवं गुना जिले में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए एनडीआरएफ की दो-दो टीमों भेजने का अनुरोध किया, गृह मंत्री शाह ने गृह मंत्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देकर दोनो जिलों में दो-दो एनडीआरएफ की टीमों तत्काल रवाना करने का निर्देश दिया।

पोल्ट्री फार्म तोड़ने के मामले में भोपाल कमिश्नर कलेक्टर सहित अन्य को अवमानना नोटिस

जागरण, जबलपुर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश ज्हीके शुक्ला की संयुक्त पीठ ने न्यायालय द्वारा पूर्व में लगाई गई रोक के बावजूद पोल्ट्री फार्म तोड़ने के मामले में भोपाल कमिश्नर केवी चौधरी, कलेक्टर अविनाश लवानिया, एएसपी (मुख्यालय) मणिका मणि कुमावत, एसडीएम गोविंदपुरा, मनोज वर्मा, तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव, आरआई मायाराम यादव और पटवारी भोला शंकर को अवमानना नोटिस जारी कर अनावेदकों को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। भोपाल के ग्राम हथाईखेड़ा, तहसील हजूर निवासी मुबारक अली की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया है कि ग्राम हथाईखेड़ा में उसकी जमीन है। उसने जमीन रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। इस मामले में एसडीएम गोविंदपुरा ने जमीन का सीमांकन कराने का आदेश दिया था। इसके बाद भी 16 जुलाई 2021 को उसका पोल्ट्री फार्म तोड़ दिया गया। मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 23 अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर प्रदेश में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई है। न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद सभी अनावेदकों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

कार्यालय अध्यक्ष, काउंसिलिंग समिति आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004	
फार्म-डी (Pharm-D) (पूर्णकालिक 6 वर्ष), एकीकृत एम.बी.ए. (IIMBA) (पूर्णकालिक 5 वर्ष) एकीकृत एम.सी.ए. (IIMCA) (पूर्णकालिक 5 वर्ष), बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी (BHMCT) (पूर्णकालिक 4 वर्ष)	
पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी (हायर सेकेण्डरी स्कूल 12वीं) परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु (मध्यप्रदेश में स्थित निजी संस्थान)	
ऑनलाइन काउंसिलिंग समय सारणी, सत्र 2021-22	

प्रथम चरण	
गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Registration)	10.08.2021 से 01.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration)	02.09.2021 से 03.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	26.08.2021 से 05.09.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी	
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	06.09.2021 दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	09.09.2021 से 15.09.2021 सायं 5:00 बजे तक

द्वितीय चरण	
गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Registration)	14.09.2021 से 20.09.2021
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration)	21.09.2021 से 22.09.2021
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	16.09.2021 से 24.09.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी	
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	25.09.2021 दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	29.09.2021 से 08.10.2021 सायं 5:00 बजे तक

संस्था स्तर की काउंसिलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।
09.10.2021 से 10.10.2021 रात्रि 11:45 बजे तक	12.10.2021 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसिलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
13.10.2021 से 14.10.2021 रात्रि 11:45 बजे तक	16.10.2021 प्रातः 10:30 बजे
<ul style="list-style-type: none"> प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अग्र्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसिलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। संस्था स्तर की काउंसिलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अग्र्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे। काउंसिलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्ती करण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। 	

(कोविड-19 के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिये, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अग्र्यर्थी को नहीं जाना है)
संपर्क : 0755-6720205, 2660441
ईमेल : dte.helpcenter@mp.gov.in.
म.प्र. माध्यम / 101567 / 2021
अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED

Regd. Office : Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie, Tehsil Sarai, District Singrauli - 486 669, (Madhya Pradesh)
Corporate Office: 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 (India)
Website: www.jppowerventures.com Email: jpv.investor@jalindia.co.in CIN : L40101MP1994PLC042920

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

(Rs. in Lakhs except Shares and EPS)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	92,635	106,309	66,309	343,437	92,641	106,313	70,014	342,901
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	719	12,493	2,330	23,222	716	12,490	3,679	22,617
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	719	36,858	2,330	47,587	716	23,605	3,679	33,732
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	452	33,364	1,439	36,628	434	20,054	3,168	22,716
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	468	33,457	1,429	36,691	450	21,625	2,648	28,206
6	Equity Share Capital	685,346	685,346	684,045	685,346	685,346	685,346	684,045	685,346
7	Other equity				(4,530)				(37,693)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (in Rs.)								
	Basic :	0.003	0.31	0.0135	0.34	0.003	0.19	0.0219	0.25
	Diluted :	0.003	0.31	0.0134	0.34	0.003	0.19	0.0217	0.25

Note : The above is an extract of the detailed statement of Quarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarter ended financial results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website i.e. www.jppowerventures.com.

Place : New Delhi
Dated : 6th August, 2021

NO DREAM TOO BIG

For and on behalf of the Board
Manoj Gaur
Chairman
DIN 0008480

HOCKEY AT OLYMPICS

US Senate to try to finish \$1 trillion infra Bill today

RICHARD COWAN & SUSAN CORNWELL
Washington, August 5

THE US SENATE, unable to finalise a \$1 trillion infrastructure Bill on Thursday, will try again on Saturday when it is scheduled to hold a vote on limiting debate and moving toward passage of the hard-fought legislation.

Senate majority leader Chuck Schumer struggled throughout the day to reach closure on a bipartisan Bill that would trigger new construction projects throughout the United States to expand or refurbish roads, highways, bridges, airports and other public works, many of them in standard condition.

Following hours of closed-door negotiations, senators failed to reach an agreement on remaining amendments to the Bill, beyond the nearly two dozen already debated this week.

"We have been trying to vote on amendments all day but have encountered numerous objections from the other side," Schumer said, referring to Republicans.

Action on the legislation, which Democratic President Joe Biden supports, was held up by a flurry of demands from various senators, including a controversial move by some Republicans demanding billions of dollars in new Defense Department improvements, according to lawmakers.



A separate disagreement over a cryptocurrency provision in the infrastructure Bill also was simmering.

Once the infrastructure Bill is voted upon, the Senate was expected to begin work on a budget framework that Democrats hope would pave the way for a \$3.5 trillion "human infrastructure" Bill later this year.

The measures must also pass the House of Representatives, where Democrats have a thin majority.

Some senior House Democrats, including Representative Peter DeFazio, chairman of the Transportation and Infrastructure Committee, have expressed concern that the \$1 trillion Bill lacks sufficient climate measures.

Earlier on Thursday, the non-partisan Congressional Budget Office said the legisla-

tion would increase federal budget deficits by \$256 billion over 10 years. Lead negotiators on the Bill disagreed, arguing the measure would be financed in a way so as not to incur deficit spending.

The sweeping package of funding is one of Biden's top legislative priorities.

The CBO's analysis said the Bill will increase Washington's revenue by \$50 billion over the decade and increase discretionary spending by \$415 billion.

It did not include \$57 billion in added revenue that senators estimated Washington would collect over the long term from the economic growth benefits of the infrastructure projects.

It also did not count \$53 billion in unused federal supplemental unemployment funds to be returned from states.

— REUTERS

China vows to supply world 2 bn jabs this year

ASSOCIATED PRESS
Taipei, Taiwan, August 6

A PLEDGE BY China to supply two billion doses of Covid-19 vaccines to other countries this year expands the commitments made by a nation that is already the largest exporter of the shots by far.

President Xi Jinping made the announcement on Thursday in a message to an international forum China organised on vaccine cooperation. He also promised to donate \$100 million to COVAX, the programme that aims to distribute vaccines to low- and middle-income countries.

"This means that China stands ready to provide safe and effective vaccines for nearly 10% of the population in the rest of the world," said Wang Xiaolong, the director general of the Foreign Ministry's Department of International Economic Affairs.

China has already delivered 770 million doses to foreign countries since September last year, Wang said at a briefing for foreign media on Friday. Most of those have been exported under bilateral deals. Wang said that donated doses are in the tens of millions, but did not provide a precise figure.

The US has donated 110 million doses, mostly through COVAX, the White House said earlier this week.

China's two biggest Covid vaccine makers, Sinopharm and Sinovac, have entered agreements to deliver up to 550 million doses through COVAX by the middle of next

year. Wang said the first deliveries under the UN-backed programme will be made this month to Bangladesh, Pakistan and Algeria.

Hundreds of millions of Chinese shots have been administered to people both in China and around the world. However, there are concerns about whether they protect adequately against the highly transmissible delta variant.

In Indonesia and Thailand, which have relied heavily on Sinovac's shot, the governments are planning to give a booster shot of the Moderna vaccine to health workers after reports that some had died despite being fully vaccinated with the Chinese shot.

The Sinovac and Sinopharm vaccines, which both use inactivated viruses, have shown lower effectiveness against the delta variant but still provide some protection, according to Feng Zijian, an official at China's Center for Disease Control, who spoke to state broadcaster CCTV in June.

Most of the more than 1.7 billion vaccine doses that have been administered in China are from Sinopharm and Sinovac. China is currently fighting a widespread outbreak driven by the delta variant, which has infected people who have been vaccinated.

Sinovac published a study online in July, which has yet to be peer-reviewed, that showed a third booster shot given at least six months after the second shot could greatly increase antibody levels

Google's Larry Page gets NZ residency, raising questions

ASSOCIATED PRESS
Wellington, August 6

GOOGLE CO-FOUNDER LARRY Page has gained New Zealand residency, officials confirmed on Friday, stoking debate over whether extremely wealthy people can essentially buy access to the country.

Immigration New Zealand said Page first applied for residency in November under a special visa open to people with at least 10 million New Zealand dollars (\$7 million) to invest.

"As he was offshore at the time, his application was not able to be processed because of Covid-19 restrictions," the agency said in a statement. "Once Mr. Page entered New Zealand, his application was able to be processed and it was approved on February 4, 2021."

Gaining New Zealand residency would not necessarily affect Page's residency status in the US or any other nations.

New Zealand lawmakers confirmed that Page and his son first arrived in the country in January after the family filed an urgent application for the son to be evacuated from Fiji due to a medical emergency.

"The day after the application was received, a New Zealand air ambulance staffed by a New Zealand ICU nurse-escort medevaced the child and an adult family member from Fiji to New Zealand," health minister Andrew Little told lawmakers in Parliament.

Little was responding to questions about how Page had managed to enter the country at a time when New Zealand had



shut its borders to non-residents in an attempt to stop the spread of the coronavirus.

Little told lawmakers the family had abided by applicable virus protocols when they arrived. Page's residency application was approved about three weeks later.

Google did not immediately respond to requests for comment.

Immigration New Zealand noted that while Page had become a resident, he didn't have permanent residency status and remained subject to certain restrictions.

Still, the agency on its website touts the "Investor Plus" visa as offering a "New Zealand lifestyle," adding that "you may be able to bring your car, boat and household items to New Zealand, free of customs charges". Some local news organisations reported that Page had since left New Zealand.

Forbes on Friday ranked Page as the world's sixth wealthiest person, with a fortune of \$117 billion. Forbes said Page stepped down as chief executive of Google's parent company Alphabet in 2019, but

remained a board member and controlling shareholder.

Opposition lawmakers said the episode raised questions about why Page was approved so quickly at a time when many skilled workers or separated family members who were desperate to enter New Zealand were being turned away.

"The government is sending a message that money is more important than doctors, fruit pickers and families who are separated from their children," ACT deputy leader Brooke van Velden said in a statement.

In 2017, it emerged that Silicon Valley billionaire Peter Thiel had been able to gain New Zealand citizenship six years earlier, despite never having lived in the country. Thiel was approved after a top lawmaker decided his entrepreneurial skills and philanthropy were valuable to the nation.

Thiel didn't even have to leave California for the ceremony; he was granted citizenship during a private ceremony held at the New Zealand Consulate in Santa Monica.

Alibaba warns investors of higher taxes as Beijing's crackdown widens

ZHEPING HUANG
August 6

ALIBABA GROUP HAS warned investors years-long government tax breaks for the internet industry will start to dwindle, adding billions of dollars in costs for China's largest corporations as Beijing extends its campaign to rein in the sector.

China's No.1 e-commerce company told investors during post-earnings calls this week that the government had stopped treating some of its businesses as so-called Key Software Enterprises (KSE) — a designation that conferred a preferential 10% tax rate, according to people familiar with the matter. The Tmall operator forecasts an effective tax rate of 20% for the September quarter, up from just 8% a year ago, the people said, asking not to be identified discussing private conversations. Going forward, Alibaba warned that most internet companies will likely no longer enjoy the 10% rate, they said.

The move reflects Beijing's tightening regulatory approach toward its largest tech companies from Alibaba to Tencent and Meituan, which have come under fire for using their troves of data to enrich investors at the expenses of users. On Thursday, the state-backed newspaper Securities Times argued in an op-ed that China should scrap tax breaks to gaming companies because now they are big



enough to thrive on their own.

"Because the preferential tax rates related to KSE are subject to annual review by the relevant tax authorities in China, there is always risk that companies that apply would not be granted the tax benefit," Citigroup analyst Alicia Yap wrote in a research note on Friday.

"The argument basis sounds reasonable given a tightening regulatory environment and recent anti-trust investigation and fines on the internet sector," Yap said.

Alibaba representatives didn't immediately respond to requests for comment. Shares of the firm erased gains immediately following the report and later traded little changed.

China's effort to free up more tax revenue reflects a global trend. A tax deal struck between the world's richest countries this year brought global governments a step closer toward clawing back some power from technology giants that have used century-

old regimes to build up wealth eclipsing the economies of most nations.

China's government has over the years handed out a wide range of tax incentives and financial aids to its now giant internet sector. While the standard corporate income tax rate in the country is 25%, those who qualify as high-tech enterprises enjoy a 15% rate and an even-more generous 10% rate is awarded to those deemed to operate essential software.

The removal of such incentives demonstrates Beijing's willingness to go after private enterprises to address social inequities and rein in powerful interests. Its campaign against big tech is now entering its 10th month, a roller-coaster ordeal that's prompting nervous investors to ponder the long-term ramification of a crackdown that quickly spread from Jack Ma's twin giants of Ant Group and Alibaba to others like Tencent and gig-economy leaders Meituan and Didi Global.

Taliban take provincial capital, kill govt officer

BLOOMBERG
August 6

THE TALIBAN CAPTURED an Afghan provincial capital and assassinated the government's top media officer in Kabul on Friday, dealing twin blows to the administration. A police spokesman in southern Nimroz province said the capital Zaranj had fallen to the hard-line Islamists because of a lack of reinforcements from the government.

Zaranj was the first provincial capital to fall to the group since the US reached a deal with the Taliban in February 2020 for a US troop pullout. A local source said the Taliban had seized the governor's office, the police headquarters and an encampment near the Iranian border.

A Taliban commander, speaking on condition of anonymity, said it has strategic importance as it is on the border with Iran. "This is the beginning and see how other provinces fall in our hands very soon," he said.

In Kabul, Taliban attackers killed Dawa Khan Menapal, head of the Government Media and Information Centre. — REUTERS

Didi weighs giving up data control to appease Beijing

BLOOMBERG
August 6

DIDI GLOBAL IS weighing giving up control of its most valuable data as part of efforts to resolve a Chinese regulatory probe into the aftermath of its controversial US initial public offering, people familiar with the matter said.

The ride-hailing giant has put forth a number of proposals to appease the powerful internet industry overseer, including ceding management of its data to a private third party, the people said, asking not to be identified talking about internal deliberations.

Regulators have signalled a preference for that third party to be state-controlled, one of the people said. It's uncertain how such an arrangement would impact Didi's access to the data, which is crucial to helping the firm orchestrate 25 million rides a day between 400 million riders and drivers.

Also unclear is whether the proposals would appease the watchdog. Didi is fighting to ensure its survival after forging ahead with its American float



despite objections from officials worried that a foreign listing could leak data and undermine national security. Regulators regarded its decision to go public despite pushback from the Cyberspace Administration of China as a challenge to Beijing.

They are weighing a range of potential punishments, including a fine, suspension of certain operations or the introduction of a state-owned investor, the people said. One proposal on the table was to bring in a state-owned firm with a larger stake than current top shareholders SoftBank Group and Uber Technologies, one of the people said. Also possible is a forced privatisation and delisting

or withdrawal of Didi's US shares.

The CAC didn't respond to a faxed request for comment, and representatives for Didi didn't respond to messages and calls seeking comment.

Deliberations are at a preliminary phase and the outcomes likely won't be finalised till after weeks or even months of review, the people said. But Beijing is likely to impose harsher sanctions on Didi than on Alibaba Group, which swallowed a record \$2.8 billion fine after a months-long antitrust investigation and agreed to initiate measures to protect merchants and customers, the people said.

Didi could serve as a test case for a broader Chinese government effort to wrest back control of the data that tech giants hoover up from hundreds of millions of users daily, a fount it considers vital to the economy and social stability.

China's government has proposed creating a joint venture with internet firms that would oversee that information, a project led by the People's Bank of China, Bloomberg News has reported.

Didi's June 30 IPO was the trigger for a renewed assault on internet giants that at one point wiped out more than \$1 trillion of market value from Chinese stocks. The subsequent wave of crackdowns on industries from private online education to ride-hailing and social media has spooked investors, prompted the Securities and Exchange Commission to more closely examine the country's companies, and all but halted a lucrative annual \$40 billion train of US floats by Chinese firms.

We had let Messi go to save the club, says Barca president

JOSEPH WALKER
Barcelona, August 6

BARCELONA WAS FORCED to let star player Lionel Messi leave the club because his high wages coupled with strict La Liga financial rules could have jeopardised its future, club president Joan Laporta said on Friday.

Both the club, which has suffered steep losses recently, and 34-year-old Messi had wanted to sign a new contract. But the Argentine's deal would have taken salaries to 110% of the club's earnings, a financially risky move given the impact of the pandemic, Laporta said.

"The club is above everything — even above the best player in the world," Laporta told a news conference. "We reached agreement, but couldn't formalise it,



A Barcelona fan displays his tattoo of Lionel Messi outside the Camp Nou in Barcelona on Friday

because of the club's economic situation, which means we can't register the player due to salary limits," he said.

Without Messi's wages, salaries would account for 95% of Barcelona's income, he said. Messi had wanted to sign a

new contract at Barcelona on reduced terms, reportedly 50% below his latest pay, but the club was unable to come up with an arrangement that also complied with the financial rules of Spain's La Liga competition.

— REUTERS

JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED

Regd. Office : Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie, Tehsil Sarai, District Singrauli - 486 669, (Madhya Pradesh)
Corporate Office : 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 (India)
Website : www.jppowerventures.com Email: jpv.investor@jalindia.co.in CIN : L40101MP1994PLC042920

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

(Rs. in Lakhs except Shares and EPS)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	92,635	106,309	66,309	343,437	92,641	106,313	70,014	342,901
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	719	12,493	2,330	23,222	716	12,490	3,679	22,617
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	719	36,858	2,330	47,587	716	23,605	3,679	33,732
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	452	33,364	1,439	36,628	434	20,054	3,168	22,716
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	468	33,457	1,429	36,691	450	21,625	2,648	28,206
6	Equity Share Capital	685,346	685,346	684,045	685,346	685,346	685,346	684,045	685,346
7	Other equity				(4,530)				(37,693)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (in Rs.)								
	Basic :	0.003	0.31	0.0135	0.34	0.003	0.19	0.0219	0.25
	Diluted :	0.003	0.31	0.0134	0.34	0.003	0.19	0.0217	0.25

Note : The above is an extract of the detailed statement of Quarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarter ended financial results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website i.e. www.jppowerventures.com.

Place : New Delhi
Dated : 6th August, 2021

NO DREAM TOO BIG

For and on behalf of the Board
Manoj Gaur
Chairman
DIN 0008480

अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकारी मीडिया विभाग के प्रमुख की हत्या की

काबुल, 6 अगस्त (एपी)।

अफगानिस्तान में तालिबान ने शुक्रवार को सरकारी मीडिया सूचना केंद्र के निदेशक की गोली मार कर हत्या कर दी। हाल के महीनों में पत्रकारों और अधिकार कार्यकर्ताओं पर किए गए शृंखलाबद्ध हमलों में हत्या की यह वारदात नवीनतम है।

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने बताया कि समूह के लड़ाकों ने दावा खान मेनापाल को मार डाला है जो स्थानीय और विदेशी मीडिया के लिए सरकार का प्रेस अभियान संचालित करते थे। मुजाहिद ने बाद में जारी एक बयान में कहा कि मेनापाल को मुजाहिदीन के एक विशेष हमले में मारा गया और उसे उसके कामों के लिए दंडित किया गया। मुजाहिद ने और अधिक जानकारी नहीं दी।

ईरान ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका का स्वागत किया

तेहरान, 6 अगस्त (भाषा)।

ईरान के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि उनका देश और भारत क्षेत्र, विशेष रूप से अफगानिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चित करने में रचनात्मक और उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। रईसी ने कहा कि तेहरान युद्धग्रस्त देश में नई दिल्ली की भूमिका का स्वागत करता है।

ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद रईसी ने जयशंकर के साथ अपनी बैठक के दौरान यह रेखांकित किया कि दोनों देशों को एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास में नए और विशिष्ट कदम उठाने चाहिए।

वहीं जयशंकर ने टवीट किया, ‘राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पद संभालने के बाद

जयशंकर ने टवीट किया, ‘राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पद संभालने के बाद शुक्रवार को उनसे आत्मीय भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्तिगत रूप से दी गई शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित कीं।’

जयशंकर रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे।

शुक्रवार को उनसे आत्मीय भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्तिगत रूप से दी गई शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित कीं।’
जयशंकर रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी और न्यायपालिका के पूर्व प्रमुख इब्राहिम रईसी ने मजलिस (संसद) में आयोजित एक समारोह में देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

जून में राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी रईसी (60) ने शानदार जीत दर्ज की थी।

जयशंकर ने कहा, ‘हमारे बीच के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता

जाहिर थी। हमारे क्षेत्रीय हितों में समान दिलचस्पी भी स्पष्ट नजर आ रही थी।’ उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा कि वह रईसी को टीम के साथ काम करने को उत्सुक हैं।

ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी क्षेत्र में भारत का प्रमुख भागीदार रहा है।

यह एक महीने में दोनों देशों के नेताओं के बीच दूसरी मुलाकात थी। जयशंकर ने गत सात जुलाई को रूस जाते हुए, रास्ते में ईरानी राजधानी में रुकने के दौरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात की थी। शुक्रवार की बैठक के दौरान, ईरानी राष्ट्रपति ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता विकसित करने में दोनों देशों के बीच नजदीकी सहयोग और समन्वय के महत्व पर जोर दिया।

पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय की पुलिस को फटकार, कहा हिंदू मंदिर पर हमले से विदेश में मुल्क की छवि खराब हुई

इस्लामाबाद, 6 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पंजाब प्रांत के एक दूरस्थ शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमले को रोकने में नाकाम रहने के लिए शुक्रवार को प्राधिकारियों की खिंचाई की और दौषियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि इस घटना ने विदेश में मुल्क की छवि खराब की है।

मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने इस्लामाबाद में मामले पर सुनवाई की। उन्होंने गुरुवार को हमले का संज्ञान लिया था। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पाकिस्तान हिंदू परिषद के संरक्षक प्रमुख डॉ. रमेश कुमार के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करने के बाद मामले पर स्वतः संज्ञान लिया।

पंजाब प्रांत के रहीमयार खान जिले में भोंग इलाके में लाठी, पत्थर और ईंट लिए सैकड़ों लोगों ने एक मंदिर पर हमला किया, उसके कुछ

हिस्सों को जलाया और मूर्तियां खंडित कीं।

एक खबर के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) इनाम गनी से पूछा, ‘प्रशासन और पुलिस क्या कर रही थी, जब मंदिर पर हमला किया गया?’ उन्होंने कहा कि इस हमले से दुनियाभर में पाकिस्तान की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

गनी ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता मंदिर के आसपास 70 हिंदुओं के घरों की रक्षा करने की थी। उन्होंने बताया कि सहायक आयुक्त और सहायक पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा, ‘अगर आयुक्त, उपायुक्त और जिला पुलिस अधिकारी काम नहीं कर सकते तो उन्हें हटाया जाना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि पुलिस ने मूकदर्शक बनने के बजाय कुछ नहीं किया और यह भी नहीं सोचा कि इससे विदेशों में देश की छवि खराब होगी।

अमेरिका : एक लाख ‘ग्रीन कार्ड’ के बर्बाद होने का खतरा

वाशिंगटन, 6 अगस्त (भाषा)।

रोजगार आधारित करीब एक लाख ग्रीन कार्ड के दो महीने के भीतर बर्बाद होने का खतरा है। इससे भारतीय आइटी पेशेवरों में नाराजगी है जिनका वैध स्थायी निवास का इंतजार अब दशकों तक के लिए बढ़ गया है।

आधिकारिक तौर पर स्थायी निवास कार्ड के तौर पर जाना जाने वाला ग्रीन कार्ड आव्रजकों को साक्ष्य के तौर पर जारी एक दस्तावेज है कि धारक को अमेरिका में स्थायी रूप से निवास करने की सुविधा दी गई है।

भारतीय पेशेवर संदीप पवार ने बताया कि इस साल आव्रजकों के लिए रोजगार आधारित कोटा 2,61,500 है जो 1,40,000 के सामान्य तौर पर कोटा

से काफी ज्यादा है।

उन्होंने कहा, ‘दुर्भाग्य से, कानून के तहत, अगर ये वीजा 30 सितंबर तक जारी नहीं किए जाते, तो ये हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं।’

उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा या यूएससीआइएस द्वारा वीजा प्रक्रिया की मौजूदा गति दिखाती है कि वे 1,00,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बेकार कर देंगे। इस तथ्य की वीजा उपयोग निर्धारित करने वाले विदेश मंत्रालय के प्रभारी ने हाल में पुष्टि भी की थी।

पवार ने खेद जताया कि अगर यूएससीआइएस या बाइडेन प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता तो इस साल उपलब्ध अतिरिक्त 1,00,000 ग्रीन कार्ड बर्बाद हो जाएंगे। इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों पर वाइट हाउस ने कोई

जवाब नहीं दिया।

इस बीच, अमेरिका में रह रहे 125 भारतीयों और चीनी नागरिकों ने प्रशासन द्वारा ग्रीन कार्ड बर्बाद होने से रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया है।

पवार ने कहा, ‘अधिकतर संभावित लाभार्थी, जैसे कि मैं, भारत से हैं। कई के जीवनसाथी भी यहां हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जो स्थायी निवासी बनने तक काम करने में असमर्थ हैं।’

उन्होंने कहा, ‘कई के बच्चे हैं जिनकी आश्रित की श्रेणी में आने वाली उम्र पार होने वाली है और उन्हें खुद से देश छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ेगा जबकि वे सिर्फ इसी देश को जानते हैं। अगर ये ग्रीन कार्ड जारी नहीं किए जाते तो नुकसान अथाह व अपूरणीय है।’

न्यायाधिकरणों के खाली पदों के मामले में केंद्र से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों को नहीं भरने को बेहद अफसोसजनक स्थिति करार देते हुए केंद्र को दस दिनों के भीतर उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उसे आशंका है कि इस संबंध में कुछ लॉबी काम कर रही है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने कहा—हमें न्यायाधिकरणों को जारी रखने या न्यायाधिकरणों को बंद करने पर एक स्पष्ट रुख पता होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है

रिक्तियों न भरने के पीछे लॉबी के प्रभाव की आशंका जताई शीर्ष न्यायायल ने

कि नौकरशाही इन न्यायाधिकरणों को नहीं चाहती है। पीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एफएटी) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) जैसे देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के रिक्त पदों का उल्लेख किया और कहा कि वह इन अर्ध-न्यायिक निकायों में नियुक्ति नहीं करने के कारण बताने के लिए शीर्ष अधिकारियों को तलब कर सकता है। पीठ ने कहा—हम उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते के भीतर आप निर्णय करेंगे और हमें अवगत कराएंगे। नहीं तो हम बहुत गंभीर हैं। हम शीर्ष अधिकारियों को पेश होने और

कारण बताने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कृपया ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें।

शीर्ष अदालत वकील अमित साहनी की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश रमण ने कहा—हमारी रजिस्ट्री ने जानकारी दी है कि 15 ट्रिव्यूनल बनाए गए हैं। कोई अध्यक्ष नहीं है। साथ ही कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिव्यूनल में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद और न्यायमूर्ति सूर्यकांत दोनों चयन समिति के सदस्य हैं और उन्होंने मई 2020 में नामों की सिफारिश की थी।

बैहिसाब दस्तावेज दाखिल करने पर अदालत नाराज

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अपने समक्ष दायर भारी-भरकम दस्तावेजों के बंडलों पर शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की और कहा कि इतनी अधिक मात्रा में सामग्रियां जजों को आतंक्रित करने के लिए पेश की जाती है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने पिछले साल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा पारित टैरिफ आदेश की वैधता से संबंधित याचिकाओं पर बंबई हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में 51 खंड दायर किए गए हैं। पीठ ने कहा—कल हमें इन सामग्रियों को लाने के लिए एक लॉरी की व्यवस्था करनी पड़ी। मामले में 51 खंडों में दस्तावेज दाखिल करने का क्या मकसद है ? अजिम इन्हें पढ़ते नहीं रह सकते है। आप इतने खंडों में दस्तावेज दायर कर डराना चाहते हैं।

न्यायिक हिरासत के दौरान, भट्ट को 1990 के हिरासत में यातना के मामले में दोषी ठहराया गया था, जबकि 1996 के मादक पदार्थ बरामदगी मामले में पहले ही बनासकांठा की निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हैं।

गुजरात कांडर के आइपीएस अधिकारी भट्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 2015 में सेवा से ‘अनधिकृत अनुपस्थिति’ के आरोप में बर्खास्त कर दिया था।

एनडीपीएस मामले में संजीव भट्ट की याचिका खारिज

अहमदाबाद, 6 अगस्त (भाषा)।

गुजरात उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के बर्खास्त अधिकारी संजीव भट्ट की एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है। इसमें मादक पदार्थ पर नियंत्रण संबंधी ‘एनडीपीएस’ कानून के तहत 1996 के एक मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में संशोधन का अनुरोध किया गया था। भट्ट की

यूपी सरकार के विशेष सचिव के खिलाफ प्राथमिकी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 अगस्त।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने अपर निजी सचिव परीक्षा, 2010 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव प्रभुनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी दी।

यह आरोप 2010 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा कराई गई परीक्षा से संबंधित हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि दो साल तक चली प्रारंभिक जांच में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ द्वारा अपराध किए जाने की पहली नजर में पुष्टि हुई है।

‘दिसंबर तक सभी पात्र लोगों का टीकाकरण’

नई दिल्ली, 6 अगस्त (भाषा)।

केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण कर लेने का भरोसा जताते हुए शुक्रवार को कहा कि इस सिलसिले में उसकी ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष और उससे ऊपर की पूरी आबादी का टीकाकरण कर लिए जाने संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए मांडविया ने कहा कि भारत

खुद को एनएचएआइ अध्यक्ष बनाने वाले व्यक्ति को सीबीआइ ने किया गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 अगस्त।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) का अध्यक्ष बताकर एक व्यक्ति से कथित तौर पर 80 लाख रुपए की ठगी की। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार झा बिहार

रेमडेसिविर की घरेलू उत्पादन क्षमता में बड़ी वृद्धि

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई के महीने में संक्रमितों के उपचार के लिए देश में रेमडेसिविर


के मधुबनी का रहने वाला है और उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय स्टील सिटी में आठ परिसरों में छापेमारी की तथा विभिन्न दस्तावेज और लगभग 200 सिम कार्ड बरामद किए। सीबीआइ प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया, ‘आरोप है कि खुद को एनएचएआइ का अध्यक्ष बनाने वाले व्यक्ति ने प्राधिकरण में एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया।

की कमी देखी गई थी लेकिन इसके बाद लगभग तीन महीनों के भीतर इस दवा के घरेलू उत्पादन की मात्रा में संक्रमितों के वृद्धि की गई। (भाषा)

सरकार ने देश में कोविड-19 के उत्पादन और उपलब्धता के अनुसार पात्र लाभार्थियों के लिए कोविड-19 टीके सुरक्षित करने के लिए सभी प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा, ‘आशा है कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोविड टीके उपलब्ध होंगे।’

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा देते हुए बताया कि कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत बायोटेक और तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।

महत्त्वपूर्ण सूचना			
सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियों को उनके समक्ष दर्शायी गई तिथियों से बहाल, चलने के दिनों में विस्तार और समय—सारणी में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है:—			
विशेष रेलगाड़ियों की बहाली			
रेलगाडी सं. एवं नाम	चलने के दिन	बहालीकरण की तिथियाँ	
02486 श्रीगंगानगर—नांदेड सुपरफास्ट विशेष	मंगलवार एवं शनिवार	10.08.2021	
02485 नांदेड—श्रीगंगानगर सुपरफास्ट विशेष	सोमवार एवं वीरवार	12.08.2021	
विशेष रेलगाड़ियों के चलने के दिनों में विस्तार			
रेलगाडी सं. एवं नाम	वर्तमान क्रिब्वंसी	परिवर्तित क्रिब्वंसी	प्रभावी तिथियाँ
04717 बीकानेर—हरिद्वार एक्सप्रेस विशेष	सोमवार	सोम, बुध, शुक्र	11.08.2021
04718 हरिद्वार—बीकानेर एक्सप्रेस विशेष	मंगलवार	मंगल, वीर, शनि	12.08.2021
09717 जयपुर—दौलतपुर चौक एक्सप्रेस विशेष	मंगल, शुक्र, रवि	प्रतिदिन	09.08.2021
09718 दौलतपुर चौक—जयपुर एक्सप्रेस विशेष	सोम, बुध, शनि	प्रतिदिन	10.08.2021
09717/09818 जयपुर—दौलतपुर चौक—जयपुर एक्सप्रेस विशेष (प्रतिदिन) की परिवर्तित समय—सारणी			
रेलगाडी सं.: 09717		रेलगाडी सं.: 09718	
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
		चंडीगढ़	19:00 19:10
		साहिबजादा अजीत सिंह नगर	18:44 18:46
		मोरिंडा	18:14 18:16
		रूपनगर	17:48 17:50
		आनन्दपुर साहिब	17:10 17:12
		नंगल डैम	16:45 16:55
11:00	11:02	ऊना हिमाचल	16:23 16:25
11:28	11:30	अब अंदीरा	15:55 15:57
11:55	---	दौलतपुर चौक	--- 15:40
नोट: उपरोक्त विशेष रेलगाड़ियों के अन्य स्टेशनों की समय—सारणी में कोई बदलवा नहीं है।			
रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों एवं उनकी विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें			
रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइज़ेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केंन्द्र सरकार के सभी नियमों और अन्य सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।			
रेलमदद वेबसाइट दर्खें: www.railmadad.indianrailways.gov.in		रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर हमें फ़ोन करें	उत्तर रेलवे आपकी सुविधा—हमारा ध्येय
रेलमदद ऐप डाउनलोड करें		ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें	

<p>JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED</p>									
<p>Regd. Office : Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie, Tehsil Sarai, District Singrauli - 486 669, (Madhya Pradesh) Corporate Office: ‘JA House’ 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 (India) Website: www.jppowerventures.com Email: jpv1.investor@jalindia.co.in CIN : L40101MP1994PLC042920</p>									
<p>STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021</p>									
(Rs. in Lakhs except Shares and EPS)									
Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	92,635	106,309	66,309	343,437	92,641	106,313	70,014	342,901
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	719	12,493	2,330	23,222	716	12,490	3,679	22,617
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	719	36,858	2,330	47,587	716	23,605	3,679	33,732
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	452	33,364	1,439	36,628	434	20,054	3,168	22,716
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	468	33,457	1,429	36,691	450	21,625	2,648	28,206
6	Equity Share Capital	685,346	685,346	684,045	685,346	685,346	685,346	684,045	685,346
7	Other equity				(4,530)				(37,693)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (in Rs.)								
	Basic :	0.003	0.31	0.0135	0.34	0.003	0.19	0.0219	0.25
	Diluted :	0.003	0.31	0.0134	0.34	0.003	0.19	0.0219	0.25
<p>Note : The above is an extract of the detailed statement of Quarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarter ended financial results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company’s website i.e. www.jppowerventures.com.</p>									
Place : New Delhi Dated : 6th August, 2021					<p>Construction Power Genest Hospitality Real Estate Fertilizer Rudra International Circuit</p> <p>For and on behalf of the Board</p> <p>Manoj Gaur Chairman DIN 00089480</p>				